



# राहत आयुक्त सम्मेलन

2 मई, 2026

आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय



# माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 प्वाइंट एजेंडा

- विकास क्षेत्रों में आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत अपनाएं
- सभी के लिए जोखिम कवरेज सुनिश्चित करें
- आपदा प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाएं
- जोखिम मानचित्रण में वैश्विक निवेश करें
- आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएं
- आपदा विषयों पर विश्वविद्यालयों का नेटवर्क विकसित करें
- सोशल मीडिया एवं मोबाइल तकनीक का उपयोग करें
- स्थानीय क्षमता एवं पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करें
- आपदाओं में अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में एकता लाएं
- आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन विकसित करें



सत्यमेव जयते

# आपदा प्रबंधन क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास

- आपदा प्रबंधन के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया
- पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रसार :
  - ✓ वर्षा, चक्रवात और बाढ़ का पूर्वानुमान, अब 7-दिन पहले ही सभी हितकारकों के साथ साझा किया जाता है
  - ✓ पूरे देश में 'कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल' आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम (CAP) लागू किया है। विभिन्न आपदाओं के बारे में लोगों तक करोड़ों अलर्ट पहुंचाए गए हैं
  - ✓ स्वदेशी सेल प्रसारण की शुरुआत आज से की जा रही है
- NDRF में 2014 के बाद से 06 अतिरिक्त वाहिनियाँ स्थापित की गयीं। NDRF में 16 प्रचालनात्मक वाहिनियां हैं
- NIDM विजयवाड़ा की स्थापना
- NDRF अकादमी की नागपुर में शुरुआत
- युवा आपदा मित्र योजना में 2,37,000 युवा आपदा-मित्रों को रजिस्टर किया गया है, 51,000 युवा आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है



# मुख्य प्राकृतिक आपदाएँ – पूर्वानुमान का अग्रिम समय

आपदा का प्रकार	प्रारंभिक चेतावनी एजेंसी	पूर्वानुमान / चेतावनी का अग्रिम समय
चक्रवात	IMD	15 दिन: संकेत 3-7 दिन (पथ एवं तीव्रता)
बाढ़ (परामर्श पूर्वानुमान)	CWC	7 दिन
लू (हीटवेव)	IMD	7 दिन
शीत लहर	IMD	7 दिन
आंधी / बिजली / ओलावृष्टि	IMD	5 दिन
भूस्खलन	GSI	48 घंटे
सुनामी	INCOIS	कुछ घंटे पहले
ऊँची लहरें, स्वेल सर्ज, तूफानी ज्वार	INCOIS	2 से 3 दिन



# आपदा प्रबंधन के फोकस क्षेत्र

- **आपदा प्रबंधन के लिए सरकार का समग्र (Whole of Government) दृष्टिकोण:** सभी राज्यों और अधिकांश जिलों ने आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार कर ली हैं। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण किया जा रहा है
- **अंतरिक्ष और नई तकनीक का दोहन:** समग्र अंतरिक्ष आधारित (SPACE BASED) परिसंपत्ति कार्यक्रम और नई प्रौद्योगिकी (ML and AI) पर विचार किया जा रहा है
- **लोकल आपदाओं पर फोकस हेतु DDMAs का सशक्तिकरण :** हीटवेव तथा लाइटनिंग आपदाओं से निपटने हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय क्षमताओं के विकास हेतु कार्य किया जा रहा है
- **आग रोकथाम पर फोकस :** राष्ट्रीय फायर पोर्टल तथा राज्यों की फायर ब्रिगेड का उन्नतीकरण
- **150 Multi Hazard Prone** जिलों में कार्ययोजना बनाकर समन्वय एवं संकल्प के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी



# आपदा प्रबंधन में चिन्हित महत्वपूर्ण सुधार के क्षेत्र

- शून्य जनहानि हेतु क्षमता निर्माण एवं पूर्व तैयारी
- विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन संबंधित measures को integrate करने की आवश्यकता है
- सभी के लिए आपदा प्रबंधन जोखिम कवरेज
- डिजास्टर मिटीगेशन पर प्रभावी निवेश करने की तथा NDMF/SDMF का सदुपयोग करने की आवश्यकता
- राष्ट्रव्यापी भूकंप early warning मॉडल का विकास किया जा रहा है
- राज्यों की मजबूत तथा व्यवहारिक डीपीआर तैयार करने की क्षमता का विकास
- राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के वित्तीय ढांचे में PFMS लागू किया जाना है
- आपदा प्रबंधन के Eco-system में निजी क्षेत्र एवं शिक्षण संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है



# राष्ट्रीय आपदा जोखिम मूल्यांकन

- NDMA द्वारा **150 Multi Hazard Prone** जिलों में कार्ययोजना बनाकर समन्वय एवं संकल्प के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी
- NDMA द्वारा National Landslide Risk Mitigation Programme के तहत Drone Lidar Technology द्वारा Landslide जोखिम मूल्यांकन किया जा रहा है। चार राज्यों में शुरुआत (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एवं सिक्किम)
- NDMA द्वारा 3 शहरों (दिल्ली, अहमदाबाद एवं मुंबई) को पूर्णतः flood proof बनाने हेतु प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं
- NRSC द्वारा 6 राज्यों (असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) के Flood Atlas जारी कर दिए गए हैं



# पिछले वर्ष किए गए सार्थक प्रयास

- **Mitigation Scheme for Forest Fire Risk Management** : 19 राज्यों के 144 जिलों में पूर्व अभ्यास, क्षमता वर्धन, जागरूकता अभियान, रिकवरी, उपकरण आदि के लिए ₹818.92 करोड़ का बजट स्वीकृत
- **Lightning Safety Mitigation Project** : 10 राज्यों के 50 lightning-prone (आकाशीय बिजली से अत्यधिक प्रभावित) जिलों में ₹186.78 करोड़ का कार्यक्रम स्वीकृत जिसके अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों के रूप में शैक्षणिक जागरूकता, क्षमता वर्धन, प्रशमन एवं अनुसंधान एवं विकास पर विशेष जोर
- **Urban Flood Risk Management Programme (UFRMP I एवं II)** : Major cities में Phase-I जारी, nature-based solutions पर मूलतः केंद्रित एवं Phase-II के अंतर्गत 11 शहरों (भोपाल, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ आदि) में ₹2,444.42 करोड़ का कार्यक्रम स्वीकृत
- **Assam Wetland Restoration & Rejuvenation Project (2025) स्वीकृत**: ₹692.05 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर (HLC द्वारा) 24 wetlands (9 जिलों में झीलों का पुनर्स्थापन), Brahmaputra नदी तंत्र में बाढ़ बचाव हेतु storage की क्षमता बढ़ाना, Flood resilience, Erosion control (कटाव नियंत्रण) और fisheries (मत्सय) विकास के लिए। (Central Share: ₹519.04 Cr)
- **National Project for strengthening Community-Based Disaster Risk Reduction(DRR) in Panchayati Raj Institutions (PRIs) (2025)** : ₹507.37 करोड़ का नया प्रोजेक्ट (MOPR + NDMA द्वारा संयुक्त रूप से) 20 राज्यों के 81 आपदा प्रवर जिलों में स्वीकृत, इसके अंतर्गत bottom-up approach से DRR (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में एकीकृत करना
- NDMA की 38 Hazard Specific Guidelines (जोखिम आधारित मार्गदर्शिका) सभी माननीय संसद सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई है



# NIDM द्वारा क्षमता निर्माण हेतु प्रयास

- वर्ष 2025-26 में 94 प्रशिक्षण कार्यक्रम किये, जिसका 5600 प्रतिभागियों ने लाभ उठाया
- 10 ई-लर्निंग पाठ्यक्रम और 8 ऑनलाइन कोर्सेज iGot प्लेटफार्म पर चल रहे हैं जिसमें 2.5 लाख प्रतिभागी enroll कर चुके हैं
- वर्ष 2025-26 में 30,000 ग्राम पंचायतों के 42,000 से अधिक प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया
- 350 यूनिवर्सिटीज एवं शैक्षिक संस्थानों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण नेटवर्क खड़ा किया है
- विदेश मंत्रालय के साथ मिल कर 2024-26 में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिसमें 20 देशों के 57 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया
- अप्रैल 2026 में NIDM को CBC के द्वारा 'अति उत्कृष्ट' 4 स्टार रेटिंग, तथा QCI के द्वारा श्रेष्ठ पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO-14001 मान्यता प्रदान की गई है



सत्यमेव जयते

# 15<sup>वें</sup> तथा 16<sup>वें</sup> वित्त आयोग के अंतर्गत आपदा प्रबंधन हेतु सिफारिशें

विषय	15 <sup>वां</sup> वित्त आयोग (FC-15)	16 <sup>वां</sup> वित्त आयोग (FC-16)
राज्य को कुल आवंटन (SDRF + SDMF) रुपये करोड़ में	1,60,153 (1,25,000 कुल जारी की गयी राशि)	2,04,401 (कुल 27.6% की वृद्धि के साथ )
कुल केंद्रीय आवंटन (NDRF + NDMF) रुपये करोड़ में	68,463 (29,000 कुल जारी की गयी राशि)	79,406 (कुल 16.0% की वृद्धि के साथ)
अप्रयुक्त शेष राशि	कोई विशेष अनुशंसा नहीं	यदि अप्रयुक्त एसडीआरएफ शेष राशि पिछले तीन वर्षों के वार्षिक आवंटन के योग से अधिक हो जाती है, तो रिलीज को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है
डेटा अनुपालन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (NDMIS) के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया	वित्तीय वर्ष के लिए अनिवार्य डेटा को अगले वर्ष की 31 मई तक NDMIS में दर्ज करना आवश्यक है
आपदा जोखिम खतरे	12 प्रमुख जोखिम (चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला/शीत लहर)	अब इसमें 14 जोखिम शामिल हैं (चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला/शीत लहर, गर्मी की लहर, बिजली का गिरना )



# 2026 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसमी वर्षा का पूर्वानुमान

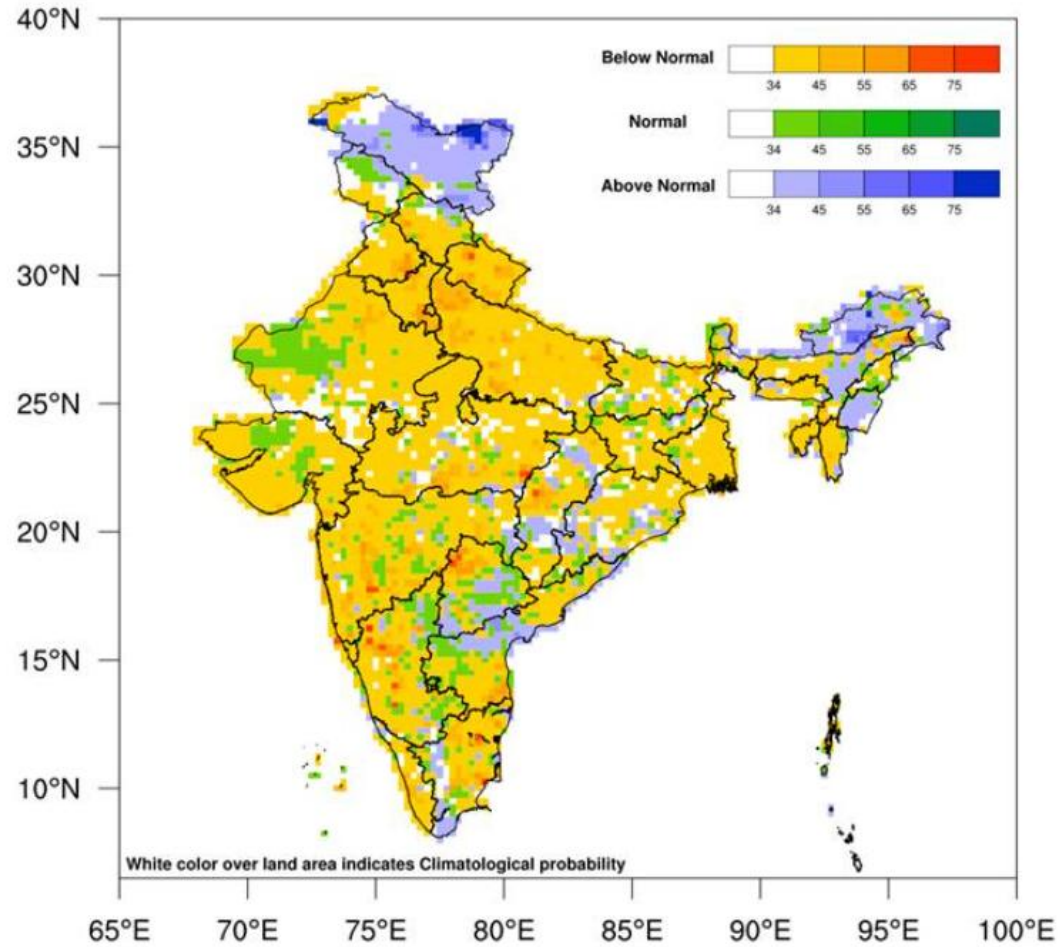
- 2026 के दौरान पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) की मौसमी वर्षा सामान्य से कम (दीर्घावधि औसत का लगभग  $92\% \pm 5\%$ ) रहने की संभावना है
- उत्तर-पूर्व भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में मौसमी वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है, जबकि इन अपवाद क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है
- नवीनतम मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली तथा अन्य जलवायु मॉडल संकेत देते हैं कि एलनीनो स्थितियों के विकसित होने की संभावना है





# 2026 IMD वर्षा पूर्वानुमान

Tercile probability rainfall forecast for 2026 southwest monsoon season





सजग नागरिक, सामुदायिक भागीदारी, उत्तरदायी  
शासन, सुरक्षित राष्ट्र

**Alert citizens, community participation,  
responsive governance, safe nation**

धन्यवाद

